संक्षिप्त समाचार

पहले कश्मीरी पंडितों को वापस लाओ फिर सीएए लागू करना : उद्धव ठाकरे

मुंबई, एजेंसी। नागरिकता संसोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी होते ही सियासत तेज हो गई। सत्ता पक्ष जहां इसका स्वागत कर रहा है, वहीं विपक्ष इसकी आलाचना कर रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इसकी आलोचना की और सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने मंगलवार को कहा, देश में नया कानून सीएए लाया गया है। जो हिंदू, सिख, पारसी और जैन देश के बाहर डरे हुए हैं, उन्हें हमारे देश में लाया जाएगा। उन्हें जरूर लाया जाए, लेकिन यह सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है। ठाकरे ने आगे कहा, जब मैं सीएम था, तो भाजपा देश में सीएए और एनआरसी का भूत लेकर आई थी। उस समय लोगों के मन में डर पैदा हो गया, खासकर असम के लोगों के मन में। इस कानून के खिलाफ कोर्ट में कई याचिकाएं हैं। अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन उन्होंने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शिवसेना (यूबीटी) सुप्रीमो ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर धर्म के नाम पर भेदभाव पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, धर्मों के बीच भेदभाव पैदा कर झगड़े और दंगे कराना चाहते हैं। आने वाले चुनाव में एक तरफ बीजेपी है जो धर्मों के बीच नफरत पैदा कर रही है और दूसरी तरफ देशभक्त इंडिया गठबंधन है। यह चुनाव देशभक्त बनाम नफरत करने वालों के बीच होने जा रहा है। अगर आप विदेशों से हिंदुओं को हमारे यहां लाना चाहते हैं तो पहले कश्मीरी पंडितों को वापस लाओ और फिर सीएए लाओ। वहीं, इस मुद्दे पर एनसीपी ने भी सरकार की आलोचना की है। सीएए की अधिसूचना जारी होने पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, अगले हफ्ते जो कुछ भी होने वाला है, जाहिर तौर पर उसका संबंध लोकसभा चुनाव से होगा। उन्होंने अब तक इसे लागू क्यों नहीं किया? देश जानना चाहता है कि चुनावी बॉन्ड और पेटीएम में क्या हुआ। सच्चाई क्या है और इसके पीछे कौन है।

घर में निकला कोबरा तो लग गई भीड़, कोई फोड़ने लगा नारियल, किसी ने पिलाना शुरू किया दूध

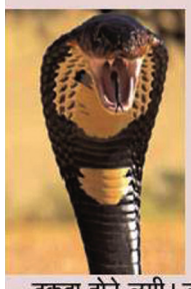

रायपुर, एजेंसी। कभी-कभी पूजा पाठ और अंधविश्वास में लोग खतरे को समझ नहीं पाते है। कुछ इसी तरह का एक मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है। जहां अंधविश्वास में गांव के लोग कोबरा सांप की पूजा करने इकट्ठा हो गए। घर में अचानक निकले सांप को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। जहरीला कोबरा लोगों को देखकर फुफकारता रहा और लोग उसके सामने कभी फूल चढ़ाते, नारियल फोड़ते तो कभी दूध पिलाने के लिए उसके पास आगे बढ़ते। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के लवन नगर पंचायत के ग्रामीण के घर जहरीला कोबरा सर्प सालों से छुपा हुआ बैठा था। जैसे ही घर वालों ने सांप को दिखा घर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जब तक घर वाले सांप को भगाने या फिर रेस्क्यू टीम को बुलाने के बारे में सोचते तब तक घर में लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। लोग सांप को दूध पिलाने के लिए आगे बढ़ने लगे तो कुछ लोग उस पर नारियल और फूल चढ़ाते हुए पूजा पाठ करने लगे। वहीं इसके बाद इस की जानकारी क्षेत्र की नगर पंचायत अध्यक्ष को लगी। वह भी कोबरा साप को देखने पहुंच गई। हैरत करने वाली बात यह है कि अध्यक्ष को लोगों को समझाने के अलावा लोगों के सांथ इस अंधविश्वास का हिस्सा बन गई। गनीमत? यह रही कि सांप ने किसी को काटा नहीं। वहीं लोग सांप पकड़ने वाले को बुलाने के बजाए उसका वीडियो बनाते रहे।

आज भाजपा में शामिल होंगी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी, पटियाला सीट से चुनाव लड़ेंगी परनीत कौर

पटियाला, एजेंसी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। उनकी बेटी जय इंदर कौर ने कल ही इस बात के संकेत दिए थे। उनसे जब उनके लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा- मैं नहीं, मेरी मां परनीत कौर पटियाला सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। वह जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। एक इंटरव्यू में उनहेंने कहा था कि मेरी बारी शायद अगले 2-3 वर्षों में आएगी। उनका इशारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव की तरफ था। वह पहले से ही निर्वाचन क्षेत्र में काम कर रही हैं। वह चार बार की सांसद हैं और अभी भी बहुत सक्रिय हैं। उनके पिता अमरिंदर सिंह से कांग्रेस ने सीएम की कुर्सी छीन ली थी। उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले पंजाब में अपनी पार्टी का गठन किया। इसके बाद उन्होंने पार्टी का विलय बीजेपी में करा लिया। इसके बाद से लगातार उनकी पत्नी के भी भाजपा जॉइन करने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि उन्होंने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सदन में लाए गए प्रस्ताव का भी समर्थन किया था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में बनी भारतीय जनता पार्टी की कमेटी के भी हिस्सा हैं। उन्होंने कल ही नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि पंजाब में बीजेपी का फिलहाल किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ है।

एकनाथ शिंदे को भाजपा ने दिया अल्टिमेटम जिससे मराठा आंदोलन भी शांत हो गया

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार ने 20 फरवरी को विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद भी मराठा आंदोलन को आगे बढ़ा रहे मनोज जारांगे पाटिल ने चेतावनी दी थी कि यह गलत तरीके से आरक्षण दिया है और 17 दिनों की भूख हड़ताल करेंगे। इससे पहले 25 जनवरी को जब वह आंदोलन का नेतृत्व करते हुए मुंबई पहुंचे थे तो उनके साथ हजारों युवाओं की भीड़ थी। ऐसी स्थिति बन गई थी कि मनोज जारांगे पाटिल के आगे सरकार दबाव में थी और उनकी बातों को मानने के लिए मजबूर थी। लेकिन फरवरी के अंत तक कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि मनोज जारांगे पाटिल अब शांत हो गए हैं। इसके अलावा मराठा आंदोलन की टेंशन से भी भाजपा मुक्त लग रही है। पर अहम सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? दरअसल इसकी शुरुआत मनोज जारांगे पाटिल के एक उकसाने वाले बयान से हुई थी। उन्होंने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया था कि वह उनकी हत्या भी करा सकते हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हुए उनके घर के घेराव की भी धमकी दी। इस बयान पर देवेंद्र फडणवीस सख्त हो गए और गृह मंत्रालय संभालने वाले डिप्टी सीएम ने बीड़ में हुई हिंसा की एसआईटी जांच का आदेश दे दिया। यह हिंसा पहले वाले मराठा आंदोलन के दौरान हुई थी। इसके अलावा एसआईटी के हेड के तौर पर नासिक के पुलिस कमिश्नर संदीप कार्णिक को जिम्मा दिया गया। उन्हें जांच के लिए तीन महीने का वक्त मिला। इसी दिन पुणे पुलिस ने जारांगे पाटिल और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इन पर आरोप था कि बिना परमिशन के इन लोगों ने 23 जनवरी को रैली निकाली थी। इस एसआईटी जांच पर मराठा समुदाय की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे भी मनोज पाटिल का हौसला कुछ कमजोर हुआ। अब बीते कुछ दिनों से वह ऐक्शन में नहीं दिख रहे हैं। एक समय में 24 घंटे मराठी चैनलों पर दिखने वाले मनोज जारांगे पाटिल ने पहले 27 फरवरी को फडणवीस का घर घेरने का फैसला टाल दिया। इसी दिन 17 दिनों की भूख हड़ताल भी वापस ले ली। कैसे भाजपा ने कर दिया मनोज जारांगे पाटिल को शांत? सरकार के सूत्र बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और कुछ अन्य भाजपा नेताओं ने एकनाथ शिंदे से इस मसले पर बात की। उन्होंने कहा कि आप मनोज पाटिल को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसा ही रहा तो हम संबंध भी खत्म कर सकते हैं। एक भाजपा ने कहा, हममें से ज्यादा लोग मानते थे कि शिंदे के साथ मनोज जारांगे पाटिल के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। पुलिस को भी इस बारे में कुछ जानकारी मिली थी। इसके बाद हमने एकनाथ शिंदे से कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आंदोलन की आड़ में अपनी छवि मजबूत करें और हमारी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दें। भाजपा ने कहा, हमारी लीडरशिप ने भी शिंदे से कहा कि वह पाटिल के मसले पर सार्वजनिक बयान दें। सरकार भी बची और विपक्ष भी आया बैकफुट पर इसके बाद ही एकनाथ शिंदे ने मनोज जारांगे पाटिल को चेतावनी दी थी कि वह हद में ही रहें। उससे बाहर निकलने पर ऐक्शन लिया जाएगा। इसके बाद जब मनोज जारांगे पाटिल के खिलाफ जांच का आदेश हुआ तो गठबंधन के वे लोग पीछे हट गए जो सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने मराठा कोटे की मांग के जवाब में ओबीसी कार्ड खेल दिया। इसे लेकर विपक्ष भी पसोपेश में आ गया और अंत में उसे मराठा कोटे पर आक्रामकता छोड़नी पड़ी। इस तरह भाजपा ने मनोज जारांगे पाटिल को हैंडल कर सरकार भी बचा ली और विपक्ष को भी बैकफुट पर धकेल दिया।

पूरे देश ने तय कर लिया है कि अबकी बार 400 पार: शाह

चंडीगढ़, । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में 'सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट' और 'विजय संकल्प सम्मेलन' को संबोधित करने के दौरान अपील किया कि, 'राज्य को देश भर में जारी विकास यात्रा का भागीदार बनाने के लिए लोक सभा चुनाव में 12 से अधिक सीटों पर कमल खिलाने का काम तेलंगाना की जनता करेगी। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धियों को देखते हुए पूरे देश ने तय कर लिया है कि अबकी बार 400 पार, एक बार फिर से नरेन्द्र मोदी सरकार।' सभी जानते हैं कि बीआरएस और कांग्रेस मजलिस के प्रभाव से चलती हैं। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तेलंगाना की जनता ने मजलिस के प्रभाव को कम करने के लिए कांग्रेस पर अपना विश्वास जताया। लेकिन तेलंगाना विधानसभा की शुरुआत होते ही, कांग्रेस ने मजलिस के नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाने का काम किया। वोट बैंक के लालच के कारण कांग्रेस और बीआरएस दोनों न तो हैदराबाद स्थापना दिवस मनाते हैं और न ही सरदार वल्लभभाई पटेल जी का सम्मान करते हैं। तेलंगाना सहित देश की जनता ने यह देखा है कि बीआरएस, कांग्रेस और मजलिस का लक्ष्य अपने परिवार को सत्ता पर बैठाना है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी। इसी तरह केसीआर के बाद केटीआर। ओवैसी की पार्टी मजलिस भी परिवारवादी पार्टी है। इन सभी पार्टियों का लक्ष्य अपने बेटे और बेटियों का कल्याण करना है। जो पार्टियाँ केवल अपने परिवार का भला सोचते हैं वे कभी तेलंगाना या देश के युवाओं, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, किसानों और दलितों का भला नहीं कर सकते। आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस ने तीन तलाक को ओवैसी और वोट बैंक के डर से नहीं हटाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक को खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। कांग्रेस 4 पीढ़ियों से सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा ही दे रही है, जबकि मोदी सरकार में गरीबों का उत्थान हुआ है। वादा चाहे धारा 370 को हटाने का हो, प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का हो, देशभर में सीएए लागू करने का हो ङ्क बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने अपना किया हर वादा निभाया है। जैसे-जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार भी बढ़ गया है। ऐसे में कमल का पताका फहराने और 2024 में एक बार फिर से नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह ने कमर कस ली है। किसी भी चुनाव से पूर्व भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह की तैयारियों, उनकी रणनीतियों और संगठन के प्रति उनकी कर्मठता को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव का परिणाम उनके हक में होगा। अमित शाह ने अपनी रणनीतियों से देश के उन राज्यों में भी भाजपा को मजबूत स्थिति में ला दिया है, जहां एक वक्त में भाजपा की स्थिति कमजोर थी। यदि भारतीय राजनीति में 'मोदी मैजिक' का अपना जादू है तो किसी भी चुनाव में वोट बटोरने के लिए अमित शाह का नाम ही काफी है।

भारत की स्वतंत्रता के 13 महीने बाद आजाद हुआ था हैदराबाद, अब मनेगा मुक्ति दिवस

हैदराबाद, एजेंसी। लोकसभा चुनावों से ऐन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को ऐलान किया कि अब हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक गजट अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा, हैदराबाद को आजाद कराने वाले शहीदों को याद करने और युवाओं के मन में देशभक्ति की लौ जगाने के लिए, केंद्र सरकार ने हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। आजादी की तारीखों का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा कि देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था लेकिन इस तारीख के 13 महीने बाद तक हैदराबाद निजाम के शासन से आजाद नहीं हो सका था। आखिरकार ऑपरेशन पोलोकी कार्रवाई के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निजाम के शासन से मुक्त हुआ। इस लड़ाई में कई जवान शहीद हो गए। उन शहीदों की याद में अब हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। उस क्षेत्र के लोग लंबे समय से यह मांग कर रहे थे। ऑपरेशन पोलोहैदराबाद रियासत को एकीकृत करने के लिए 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई एक सैन्य कार्रवाई का कोड नेम था। 15 अगस्त, 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब हैदराबाद के निजाम भारत में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे।

चुनाव आयोग से जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ विधानसभा चुनाव कराने का आग्रह

जम्मू, एजेंसी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों जम्मू-कश्मीर के तीन दिवसीय दौरे पर है। केंद्र शासित प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोग के अधिकारियों ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ दो दिवसीय परामर्श शुरू किया। इस दौरान भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने आयोग से जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ विधानसभा चुनाव कराने का आग्रह किया। भाजपा ने भी लोकसभा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने पर सहमति जताई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात करने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पार्टी नेता और पूर्व मंत्री नासिर असलम वानी ने कहा कि उन्होंने निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनावों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की भी मांग की है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद वानी ने कहा, यहां के लोगों को करीब एक दशक से अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं मिल सका है। इसलिए हमने सुझाव दिया कि लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव भी कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, अगर प्रधानमंत्री मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत जम्मू-कश्मीर से करें। उन्होंने यह भी कहा कि दो बार अलग-अलग चुनाव कराने से जम्मू-कश्मीर में आर्थिक गतिविधि, खासकर पर्यटन बाधित होगा। दूसरी तरफ, पीडीपी नेता गुलाम नबी लोन हंजुरा ने कहा कि उनकी पार्टी ने भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की वकालत की। बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''इस पर अब निर्वाचन आयोग को फैसला करना है।'' भाजपा नेता आरएस पठानिया ने कहा कि पार्टी एक साथ चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेन्स, पीडीपी और कांग्रेस धोखेबाज है जिन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आधे-अधूरे सच के नाम पर झूठ फैलाया है। भाजपा नेता ने मांग की कि केंद्र शासित प्रदेश के बाहर उन स्थानों पर मतदान केंद्र स्थापित किए जाएं, जहां कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्य रह रहे हैं ताकि उन्हें मतदान करने में आसानी हो। अधिकारियों ने बताया कि राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनावी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करेगा। बुधवार शाम को निर्वाचन आयोग के अधिकारी जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोल और राज्य पुलिस के नोडल अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। चुनाव बाद राज्य में पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी थी। हालांकि, 2018 के जून में गठबंधन सरकार गिर गई अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया था।

वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा केरल, एकमुश्त पैकेज दे दो, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर सरकार को आपत्ति

नईदिल्ली, एजेंसी। केरल इस समय अत्यधिक वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा है। इसकी प्रमुख वजह ये है कि केंद्र सरकार ने उसकी उधार लेने की क्षमता पर एक सीमा लगा रखी है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए केरल सरकार को 31 मार्च तक एकमुश्त पैकेज देने पर विचार करे। केरल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ अपने लंबित मुकदमे का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य को जरूरी राशि नहीं जारी कर रही है। पीठ ने राज्य सरकार की याचिका बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताते हुए कहा कि केंद्र थोड़ा उदार रुख अपनाते हुए केरल को विशेष मामले के रूप में एकमुश्त पैकेज दे सकता है। पीठ ने कहा कि आने वाले बजट में अधिक कठोर शर्तें रखी जा सकती हैं लेकिन 31 मार्च से पहले राज्य को एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि वह

वित्तीय समस्याओं से निपट सके। इस पर केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने कहा कि ऑफसेटिंग बैलेंस का केरल के वित्त पर असर पड़ रहा है और राज्य ने राजकोषीय सशक्तीकरण को दो बार टाल दिया है। ऑफसेटिंग बैलेंस वह न्यूनतम राशि होती है जिसे ऋण देने की एक शर्त के रूप में उधारकर्ता को जमा रखने की जरूरत होती है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने केरल को विशेष सुविधा देने में केंद्र की आपत्ति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अन्य राज्यों के इसी तरह के बेल-आउट पैकेज के अनुरोध को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बेहद मजबूर है और वह राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। अदालत ने सरकार से सभी संभावनाएं तलाशने और बुधवार को अदालत को जानकारी देने को कहा। केरल सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर केंद्र सरकार पर कर्ज लेने की सीमा लगाकर राज्य के वित्त को विनियमित करने के लिए अपनी 'विशेष, स्वायत्त और पूर्ण शक्तियों' के प्रयोग में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है। आठ मार्च को केंद्र ने केरल सरकार से कहा था कि वह 19,370 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उधार लेने की राज्य की मांग को लेकर सहमति नहीं दे सकता। केंद्रीय वित्त सचिव ने केरल के मुख्य सचिव वी वेणु की अगुवाई में आए अधिकारियों के एक दल को नयी दिल्ली में बैठक के दौरान यह जानकारी दी। बाद में वेणु ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे 19,370 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

सर्वे के मुताबिक हिमाचल में क्लीन स्वीप कर सकती है भाजपा

शिमला, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में सबकुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। दरअसल, कुछ दिनों पहले कांग्रेस के छह विधायकों ने बगावत कर दिया। उस दिन से ही बागियों और सीएम सुक्खू के बीच शब्द बाण चल रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक ताजा सर्वे आया है। इस सर्वे में कांग्रेस को एक जोर का झटका लगा है। सर्वे के मुताबिक, राज्य में कांग्रेस की इकलौती सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह की लोकसभा सीट पर भाजपा जीत दर्ज कर सकती है।

भाजपा का क्लीन स्वीप : एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक, लोकसभा चुनाव 2024 में हिमाचल प्रदेश की सभी चार लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जीत दर्ज कर सकती है। वहीं बात अगर वोट शेयर की करें तो आगामी चुनाव में भाजपा को 66 फीसदी वोट मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 33 परसेंट वोट जा सकते हैं। अन्य को 1 फीसदी वोट मिल सकता है।

प्रतिभा सिंह भी नहीं बचा पाएंगी अपनी सीट : हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन लोकसभा की चार सीटों में फिलहाल तीन पर भाजपा का कब्जा है। केवल मंडी सीट से प्रतिभा सिंह सांसद हैं। दरअसल, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी चार सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी लेकिन 2021 में मंडी सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें प्रतिभा सिंह जीत गई। लेकिन अगर यह सर्वे सच होता है तो मंडी सीट पर कांग्रेस के हाथ से जा सकती है।

20 साल पहले सीट पर कब्जा : प्रतिभा सिंह मंडी सीट से पहली बार साल 2004 में चुनाव जीती थीं। इसके बाद 2009 में उनके पति वीरभद्र सिंह जीते। वहीं 2012 दिसंबर के विधानसभा चुनाव में जीतने पर वीरभद्र सिंह सीएम बने और 2013 में मंडी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में प्रतिभा सिंह जीतीं। इस सीट से साल 2014 में प्रतिभा की हार हुई। 2019 में कांग्रेस ने इस सीट से आश्रय शर्मा उतारा, लेकिन उनकी हार हुई। इसके बाद 2021 में हुए उपचुनाव में इस सीट पर प्रतिभा सिंह ने फिर कब्जा किया। ऐसा कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद प्रतिभा गुट के नेता उन्हें सीएम बनाना चाहते थे। हालांकि आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भरोसा जताया। बीते दिनों प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भी सुक्खू कैबिनेट से रोते हुए इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सुक्खू सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। हालांकि बाद में आलाकमान की बैठक के बाद विक्रमादित्य के तेवर थोड़े नर्म दिखे।

राजस्थान की पहली लिस्ट में बोल्ड फैसला क्यों नहीं ले पाए राहुल गांधी?

नईदिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने राजस्थान की कुल 25 में से 10 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इस बार वैभव गहलोत को छोड़कर सभी नए चेहरों पर दांव लगाया है। इसमें तीन पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी बोल्ड फैसला क्यों नहीं ले पाए है? सूची को देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस आलाकमान ने गहलोत-पायलट कैंप के नेताओं को टिकट दिए है। गहलोत कैबिनेट के तीन हारे हुए मंत्रियों को टिकट दिया है। चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना, झालावाड़ से प्रमोद जैन भाया और बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल। तीनों नेता इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए थे। लेकिन पार्टी ने फिर मौका दिया है। नए चेहरों को मौका नहीं दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि तीनों ही नेता गहलोत कैंप के माने जाते है। पार्टी ने युवा के साथ-साथ अनुभव की भी अनदेखी नहीं की है। झुंझुनूं से बृजेंद्र सिंह ओला, टोंक-सवाई माधोपुर से हरीश मीणा और चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना को टिकट दिया है। तीनों नेताओं की उम्र 70 पार की है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राहुल गांधी का सूची में असर नहीं दिखाई दे रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि गहलोत-पायलट कैंप के खुश करने

के लिए ही राहुल गांधी दूर रहे हैं। गहलोत-पायलट ने जिन नामों का सुझाव दिया, उन्हें ही टिकट मिला है। 10 उम्मीदवार किसी न किसी कैंप से जुड़े हुए है। अलवर से ललित यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के करीबी माने जाते है। जबकि बृजेंद्र ओला और हरीश मीणा पायलट कैंप के माने जाते है। बाकि उम्मीदवार गहलोत कैंप के माने जाते है। फिलहाल पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर साफ कर दिया है सीनियर नेताओं को चुनाव नहीं लडाया जाएगा। पहले गहलोत, पायलट और डोटासरा के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, लेकिन पार्टी ने नए लोगों को टिकट दिया है। खास बात यह है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में किसी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। पहली लिस्ट में किसी अल्पसंख्यक को भी टिकट नहीं दिया गया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान कांग्रेस में गहलोत-पायलट कैंप के बीच खींचतान जगजाहिर है। टिकट बंटवारे से लेकर राजनीतिक नियुक्तियों में दोनों कैंप के नेताओं को जगह मिलती रही है। कभी गहलोत भारी पड़ जाते है तो कभी सचिन पायलट। विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने युवाओं को टिकट देने की मांग की थी। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार पायलट कैंप के दोनों नेता हरीश मीणा और बृजेंद्र ओला 70 पार के है। दोनों ही विधायक है। सचिन पायलट ने जब 2019 में बगावत की थी तो उस दोनों विधायक गुड़गांव के मानेसर में ठहरे थे। हालांकि, बाद में दोनों कैंप के बीच सुलह हो गई थी।